The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): They have nothing to do with import licences. Accounting will be done at the end of the year and whatever payment is made, it will be made in Canadian dollars to our country.

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान के साथ यह सर्विस कब तक शुरू होगी ?

Mr. Speaker: Next question.

Economy Drive

+

***150. Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has imposed a ban on the recruitment of fresh staff;

(b) if so, for how long; and

(c) whether Government have made any exception to the appointments being made in special cases?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) There is at present no ban on fresh recruitment except in respect of recruitment of peons from the open market.

(b) Since September, 1958.

(c) Yes.

श्री विभूति मिश्र: मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया, उस से मालूम होता है कि केवल पियन लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन गरीबों के लिए रोज़ी-रोटी का कोई दूसरा इन्तजाम कर रही है ?

Shri P. S. Naskar: Perhaps the hon. Member is mentioning about restrictions on the creation of new posts. There is a ban not only on the creation of new posts for Class IV staff, but also on the creation of new posts in higher categories, except for security and plan schemes.

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने इस बारे में अच्छी तरह से छान-बीन कर ली है कि क्या क्लास 1 और 2 के एम्पलाईज जरूरत से ज्यादा नहीं हैं ? यदि वे जरूरत से ज्यादा हैं, तो वे कितने हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पियन लोगों की भर्ती न करने से सरकार को कितने रुपये की बचत होगी ?

Shri P. S. Naskar: The staff position in the government offices in and outside Delhi has been reviewed and is being reviewed from time to time. There are four categories from Class I to Class IV. I cannot give the exact figures as to how much we have spent on the administrative cost. I have not got the figures.

श्री क० ना० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल सर्विसिज में कुछ रिट्रेंचमेंट हुई है ; यदि हां, तो उस का नम्बर क्या है और किस कैटेगरी के एम्पलाईज की रिट्रेंचमेंट हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): कोई रिट्रेंचमेंट नहीं हुई है ।

श्री म० ला० द्विवेदी: क्या सरकार ने इस बात की भी कोई जांच-पड़ताल की है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अव्वल दर्जे का स्टाफ और क्लैरिकल स्टाफ़ सरप्लस है; यदि हां, तो उस का क्या फल हुआ और उस सरप्लस स्टाफ़ का क्या किया जायेगा ?

श्री हाथी: फ़िनांस मिनिस्ट्री की ओर से एक टीम काम कर रही है, जो कि हर एक मंत्रालय को देखती है । हर एक मंत्रालय में जितनी जगह जरूरत से ज्यादा होती हैं, उन को सरप्लस करार दिया जाता है । लेकिन अभी किसी का रिट्रेंचमेंट नहीं किया गया है । यह व्यवस्था की गई है कि उन को ट्रेनिंग दी जायेगी और जहां किसी दूसरी जगह जरूरत होगी, वहां उन को रखा जायेगा ।

श्री द्वा० ना० तिवारी: क्या बहाली की रुकावट केवल सैंट्रल सर्विसिज में ही सीमित है या इस को गवर्नमेंट के अधीनस्थ पब्लिक अंडरटेकिंग में भी लागू किया जाता है ?

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether any assessment has been made to find out what impact these bans and other steps which have been taken by the Finance Ministry and the Home Ministry regarding economy drive have made and, if they have not made any impact, why not?

Shri P. S. Naskar: These steps were taken to effect economy in administrative expenditure. I have not got exact figures as to how much money has been saved.

Shrimati Savitri Nigam: The notice was given one month ago. Why is it that the Minister has not been able to find out the actual figures?

Shri Hari Vishnu Kamath: Answering a question with the same caption "economy drive" in the last session, on the 9th of December the Minister of State for Finance, Shri Bhagat, stated:

> "A Committee has been appointed under the chairmanship of the Cabinet Secretary to discuss with the administrative Ministries and take steps to curtail or suspend activities which can be dispensed with. The Committee has before it a target of reducing the non-Plan budgets of the Ministries by 10 to 15 per cent of the current year's provision."

Has any progress been made, has anything been done at all in this direction?

Shri Hathi: As I said, the Committee is reviewing the needs of each Ministry. Whenever they find that the number of staff is more than necessary it is declared surplus for that Ministry. There are two separate questions—one is the ban on creation of posts; that is there and no fresh post is created or allowed to be created.

Shri Hari Vishnu Kamath: But the aspects are complementary.

Shri Hathi: They are complementary, no doubt; but they are separate. So, if it is required for a Plan project or for security, a fresh post is created; not otherwise. So far as recruitment is concerned, there is no ban as such and we always have examinations by UPSC for recruitment to IAS, IPS etc. because people retire and those posts have to be filled up. Therefore, there cannot be any ban on recruitment. The ban is on the creation of posts.

श्री काशी राम गुप्त : मंत्री महोदय ने बताया है कि चपरासियों की भर्ती के बारे में प्रतिबन्ध है और उन की कुछ कमी भी की गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किसी लम्बी नीति के आधार पर किया गया है या किसी तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है और यह व्यवस्था कब तक रहेगी ।

श्री हाथी : इस बारे में कोई समिति नहीं बनाई गई है, लेकिन 1958 से चपरासियों की की संख्या बहुत बढ़ रही है — आफिसर्ज कम है और चपरासी ज्यादा हैं । इस लिए यह सोचा गया कि इतने चपरासियों की जरूरत नहीं है और अब रीआर्गनाइजेशन कर के दफ्तर में कम चपरासी काम करेंगे ।

श्री काशी राम गुप्त : ऐसा किस नीति के आधार पर किया गया है ?

Shri Daji: Is it not a fact that under this scheme the Government has proposed what is known as the office-oriented scheme, threatening the employment of 10,000 clerical staff and the employees have submitted a memorandum to the Home Minister? What has happened to that scheme?

Shri Hathi: Actually, that is not covered by this scheme. A separate question has been tabled today on

that subject. But, Sir, if you desire, I would answer this question.

Mr. Speaker: Yes.

Shri Hathi: The officer-oriented scheme is an experiment which we are studying in the Works, Housing Ministry. Under that scheme we do away with some of the tiers through which the file passes before reaching an officer of the status of Deputy Secretary or Joint Secretary so that the time taken in disposing of cases may be decreased. If that scheme is implemented some of the Assistants will be rendered surplus. For the surplus staff we are having a common cell where they will be given suitable training and absorbed in other places. There will not be any retrenchment.

Shri Ranga: In view of the fact that this so-called economy drive as well as ban and non-recruiting of people unnecessarily, all these were as old as Pantji's Home Ministership —at that time also these things were doled out to us—how is it that all these years Government has not declared any definite policy of not replacing wastage so that it would be possible for them to economise, in view of the fact that there is wastage all these years and superfluous staff in one Ministry or the other?

Shri Hathi: As I said, we are not doing replacement in some cases so that over-staffing may not be there.

दिल्ली में विक्रय-कर में वृद्धि

\+

*151. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ह० चं० सामन्त :
श्री बागड़ी :

श्री रामसेवक यादव :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विक्रय-कर में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह विक्रय-कर किन वस्तुओं पर बढ़ाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) जून, 1963 से दिल्ली में विक्रयकर की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई । अतिरिक्त साधनों में वृद्धि करने तथा दिल्ली और उसके पड़ौसी राज्यों में कर की दरों में विषमता को कम करने की दृष्टि से वर्तमान दरों में कुछ परिवर्तन करने के कुछ सुझाव विचाराधीन हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ सुझाव विचाराधीन हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन पर कब तक अंतिम निर्णय हो जाएगा ?

श्री हाथी : अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है । लेकिन बातचीत हो गई है । इसके बाद निर्णय लिया जाएगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि सरकार ने बिक्री कर तो बढ़ाया नहीं लेकिन बाजार में मूल्यों में वृद्धि हो गई है ? यदि हां तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्री हाथी : वह तो दूसरा प्रश्न है । लेकिन बिक्री कर बढ़ाने की जो बात है, उसका एक कारण यह है कि पंजाब, राजस्थान,